families and their major sons; subsistence allowance, compensation under the Land Acquisition Act, Preference in employment and civic amenities like primary schools, panchayat ghar, dispensary, seeds store, children's park, village pond, drinking water well, approach roads and tree platforms etc.

(c) Out of 4600 Project Affected Families in Gujarat, so far 4248 families have been allotted house plots and 4295 families have been allotted agricultural land upto 30th June, 1994.

(d) As per the Action Plan for Resettlement and Rehabilitation of Sardar Sarovar Project Affected Families drawn up by the State Government of Gujarat, all the oustees in Gujarat are expected to be rahabilitated during 1994-95.

तीस्ता परियोजना

2620. **श्री सोमपाल:**
श्री शारदा मुदुली:
डा. नौनिहाल सिंह:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीस्ता परियोजना के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है जो कि पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण सिंचाई और विद्युत परियोजना है;

(ख) इस परियोजना की संकल्पना कब की गई थी और इससे प्राप्त होने वाले बहु उद्देशीय लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको पूरा करने का आरम्भिक लक्ष्य क्या था और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इससे किन-किन राज्यों को कितना-कितना लाभ होगा; और

(ङ) इसमें हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं और इन कारणों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) इस परियोजना को सिंचाई, जल विद्युत तथा आन्तरिक नौवहन लाभ प्रदान करने वाली बहु प्रयोजनी परियोजना के रूप में वर्ष 1973 में तैयार किया गया था। तथापि, केवल तीस्ता बराज परियोजना को शुरू किया गया है। इससे 5.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है। तीस्ता, महानन्दा और डौक बराजों पर कार्य पूर्ण हो गए हैं। तीस्ता महानन्दा सम्पर्क नहर और महानन्दा मुख्य नहर पर कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं, लेकिन डौक नगर मुख्य नहर और तीस्ता जलाशय मुख्य नहर पर कार्य पूर्ण होने के भिन्न-भिन्न चरणों में है। नगर टंगोन मुख्य नहर पर कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(ग) मूलत: इस परियोजना को सातवीं योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य था। अब इसे आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(घ) परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 695 करोड़ रूपए है । पूर्ण होने पर यह परियोजना पश्चिम बंगाल में 5.27 लाख हेक्टेयर तथा बिहार में 0.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी। मार्च, 1994 तक इस परियोजना पर किया गया कुल व्यय लगभग 459 करोड़ रूपए है।

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारण वित्तीय बाधाएं, भूमि अधिग्रहण तथा वन स्वीकृति समस्यायें हैं।

जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास

2621. **श्री भिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु कोई राज्य-वार कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास हेतु गठित राष्ट्रीय स्तर की समितियों के नाम क्या-क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख) जल संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास कार्यक्रम राज्यवार नहीं है किन्तु पता लगाये गये महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के अनुसंधान संगठन इसमें भाग ले रहे हैं।

(ग) जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए अभी तक निम्नलिखित पांच भारतीय राष्ट्रीय समितियां गठित की गयी हैं: